2 पुलिस दमन बन्द किया जाए और पुलिस द्वारा मजदूरों और उनके नेताओं पर झूठे मुकदमे वापिस लिए जाएं ।

3 17 अक्तूबर 1979 कांड के शहीद मजदूरों के परिवारों को सरकार द्वारा तय समझौते के तहत दस हजार रुपये मुआवजा दिया जाए ।

4 17 अक्तूबर 1979 कांड की न्यायिक जांच कराई जाए ।

5 उक्त कांड के मजदूरों एवं मजदूर नेताओं पर चलाए जा रहे झूठे मुकदमे वापिस लिए जाएं ।

(iv) REPORTED SHORTAGE OF EXERCISE BOOKS AND TEXT-BOOKS IN UTTAR PRADESH.

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : उत्तर प्रदेश में इस वर्ष अभ्यास पुस्तिकाओं एवं पाठ्य पुस्तकों का अभूतपूर्व अभाव पैदा हो गया है । प्रदेश के बाजारों में नियंत्रित मूल्य की पुस्तिकायें खोजने पर भी नहीं मिलेंगी । प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने जून में ही यह आशंका व्यक्त की थी कि पुस्तिकाओं का अभाव होने की सम्भावना है। उन्होंने नियंत्रित कागज के कोटे में वृद्धि की मांग केन्द्रीय सरकार से की थी तथा नियंत्रित कागज की पूर्ति भी तत्काल करने का आग्रह किया था । सरकार द्वारा समय पर ध्यान न देने से यह स्थिति और गम्भीर हो गई । इस संकट के लिए केन्द्रीय एवं प्रान्तीय दोनों सरकारें उत्तरदायी हैं । यह सर्वविदित है कि जुलाई से शिक्षा सत्र प्रारम्भ होता है और उसी समय सभी विद्यार्थी उत्तर पुस्तिकाओं एवं पाठ्य पुस्तकों का क्रय करते हैं । फिर पुस्तिकाओं की आपूर्ति में इस प्रकार की अनुत्तरदायित्व पूर्ण शिथिलिता क्यों हुई ? नियंत्रित कागज की पुस्तिकाओं के अभाव में अनियंत्रित कागज से बनी पुस्तिकाओं, जिन का निर्माण बड़ी तेजी से हो रहा है का विक्रय करके व्यापारी निर्धन छात्रों एवं अभिभावकों का गहन शोषण कर रहे हैं । माननीय शिक्षा मंत्री कृपया इस बात को स्पष्ट करें कि केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न प्रान्तों को कागज का कोटा किन-किन आधारों पर निश्चित किया जाता है ? उत्तर प्रदेश के क्षेत्र एवं उसकी जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए उसके साथ न्याय क्यों नहीं किया गया ?

अनियंत्रित कागज द्वारा तैयार की गई पुस्तिकाओं का एक ओर तो निर्माताओं ने आकार (लम्बाई एवं चौड़ाई दोनों) को बहुत छोटा कर दिया है और दूसरी ओर उनके मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि कर दी है । गत वर्ष नियंत्रित कागज से बनी हुई पुस्तिकायें सर्वत्र उपलब्ध थीं । 64 पृष्ठ की अभ्यास पुस्तिका तीस पैसे में प्रत्येक विक्रेता के यहां मिल जाती थी । इस वर्ष उन पुस्तिकाओं के अभाव में 80 पृष्ठ वाली अनियंत्रित पुस्तिका जिस का आकार नियंत्रित पुस्तिका से काफी छोटा है, बाजार में एक रुपये में बिक रही है । इसी प्रकार पाठ्य पुस्तकों का भी अभाव उत्पन्न हो गया है । पुस्तकों के मूल्य में डेढ़ से ले कर अढ़ाई गुना तक की वृद्धि देखने में आई है । सरकार का ध्यान इस ओर भी जाना चाहिये कि जिन पुस्तकों का मुद्रण गत वर्ष या इसके पूर्व हो गया था, वे पुस्तकें भी इस वर्ष बढ़े हुए मूल्य छाप कर बेची जा रही हैं ।

उत्तर प्रदेश में नियंत्रित पुस्तिकाओं का वितरण सरकार सहकारी संघों द्वारा कराने जा रही है, जिन पर से जन साधारण का विश्वास उठ चुका है । वितरण प्रणाली भयंकर दोषों से ग्रस्त है । नगरों के विभिन्न क्षेत्रों एवं सुदूर गांवों के विद्यार्थियों को ये पुस्तिकायें किस प्रकार उपलब्ध हो सकेंगी, सम्भवतः सरकार ने इस पर चिन्तन करने का कष्ट नहीं उठाया है । भयंकर आर्थिक तनाव में जी रहे अभिभावकों एवं छात्रों का यह शोषण सरकार की शिक्षा के प्रति उपेक्षा, कच्छप गति एवं कल्पना शून्यता का परिणाम है। माननीय शिक्षा मंत्री इस सम्बन्ध में कृपया एक वक्तव्य दें और यह आश्वासन दें कि उचित मूल्य की शिक्षा सामग्रियों के अभाव में छात्रों एवं अभिभावकों का और अधिक शोषण नहीं होगा ।

(v) NEED FOR RUNNING ADDITIONAL TRAINS BETWEEN BANKURA AND RAINA ON BANKURA DAMODAR RAILWAY LINE.

SHRI AJIT KUMAR SAHA (Vishnupur) : Earlier, three pairs of tr ins were running in the Bankura-Damodar Railway linc between Bankura and Raina. But at present only towo pairs of trains are being run causing great hardship to a large number of peole of the area, particularly the agricultural labourers and the tribal people who move in large numbers during sowing and harvesting season. There is no other means of communication for these people and others. The divisional superintendne of Adra division, South Eastern Railway had promised to run trains in the above railway line by diesel engines, which unfortunately has not yet been implemented, nor the line is being properly maintained. Even routine maintenance work has not been done for a long time.

I, therefore, would like to request the Railway Minister to look into the matter and see that atleast three pairs of trains are run for the convenience of the poor agricultural labour and others.